

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या /2023
राज्य बनाम रमेश तोमर आदि

मु0अ0सं0 57 /2023
अं0धारा 146,147,188,324,332,353,427,341 व 34 भा0दसं0,
व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति व नुकसान का निवारण अधिनियम,
तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम
थाना कोतवाली-देहरादून।

दिनांक 15.02.2023

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. रमेश तोमर, 2. लूसून टोडरिया, 3. हरिओम भट्ट, 4. मोहन कैथोला, 5. बाबी पंवार 6. नितिन दत्त, 7. राम कण्डवाल की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 57 /2023, अं0/धारा अं0धारा 146,147,188, 324, 332,353,427,341 व 34 भा0दसं0, 1860, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम अंतर्गत थाना कोतवाली, जरिये विद्वान अधिवक्त श्री मनमोहन सिंह कर्णवाल, श्री अनिल कुमार शर्मा, अजय त्यागी, आशीष गुप्ता, दीपक गुप्ता यह कहते हुए प्रस्तुत किया है, कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। वे उपरोक्त पते के निवासी हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह न्यायालय के आदेशानुसार अपनी जमानत देने को तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

3. विवेचक थाना कोतवाली, जरिये अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता मनादुली लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास का विवरण अंकित किया गया है। जो निम्न प्रकार है:

अभियुक्त बाबी पंवार के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 40/2020 धारा 147,332,353,342 309 भा0द0सं0,1860 थाना डालनवाला।
2. मु0अ0सं0 274/2002, धारा 147,186 व 341 भा0द0सं0,1860 थाना डालनवाला।
3. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186, 188,283,390 व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली।
4. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम।

अभियुक्त शुभम नेगी के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186, 188,283,390 व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली।
2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम।

अभियुक्त नितिन दत्त के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390 व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।

2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम ।

अभियुक्त राम कण्डवाल के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390 व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।

2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम ।

अभियुक्त मोहन कैन्थुला के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 56/2003, धारा 147,186 ,188,283,390 व 341 भा0द0सं0,1860 थाना कोतवाली ।

2. मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147,186,188,332,341,34,353, 427 भा0द0सं0,1860, धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम ।

तथा कथन किया कि जमानत पर छोड़े जाने पर अभियुक्तगण द्वारा पुनः अपराध के पुनरावृत्ति करने की पूर्ण संभावना है। उक्त आधार पर जमानत का विरोध किया गया है।

4. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है, कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/20023, अं0/धारा अं0धारा 146,147,188, 307, 332,353,427,341 व 34 भा0दसं0, 1860, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति को नुकसान का निवरण अधिनियम, 1984 तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम, यह कहते हुए, दर्ज कराई गई है, कि अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कर, आने जाने वालों का रास्ता अवरुद्ध कर, धरना, प्रदर्शन किया गया। पुलिस के उच्चाधिकारियों व प्रशासन के अन्य अधिकारियों के द्वारा समझाने पर उनके सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया तथा मारपीट कर वर्दी भाड़ दिया तथा पत्थर फेंक कर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है।

6. अभियुक्तगण पर आरोप है, कि उनके द्वारा उग्रतापूर्ण आंदोलन कर, सरकारी सम्पत्ति को क्षति कारित की गई है। इस संबंध में प्रस्तुत आख्या व उपलब्ध प्रपत्रों में सरकारी सम्पत्ति का निवरण तथा नुकसान का अनुमान का कोई उल्लेख नहीं है।

7. अभियुक्तगण पर दौराने आंदोलन पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने का आक्षेप है। उपलब्ध अभिलेखों में ऐसी वर्दी या ऐस अन्य कोई चीज कब्जे में नहीं लिया गया है। जहाँ तक पत्थरबाजी किये जाने से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर गम्भीर चोट कारित किये जाने का

प्रश्न है? इस संबंध में चोटिलो के मेडिकल प्रस्तुत किये गये है। जिनमें चोटिलो पर सामान्य चोट होना दर्शित किया है। इस परिपेक्ष में बचाव पक्ष के वि० अधिवक्तागण का कथन है कि घटना के पश्चात पुलिस विभाग द्वारा आंदोलन में पत्थरबाजी करने वाले तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षतिकारित करने वाले 10 लोगो को चिन्हित किया गया है, तथा अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित किये गये व्यक्तियों में से कोई भी विरुद्ध अभियुक्तगण नहीं है। बचाव पक्ष के वि० अधिवक्तागण ने घटना स्थल पर शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन करना स्वीकार किया है। धरना, प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन करने वालों की सुरक्षा के साथ-साथ, शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन में अराजकता करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का दायित्व पुलिस पर है।

8. एफ०आई०आर० 13 नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज की गई है। एफ०आई०आर० में नामजद अभियुक्तगण के विशिष्ट कृत्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात् वर्तमान अभियुक्तगण के विरुद्ध अतिरिक्त अथवा विशेष तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. 5 अभियुक्तगण का आपराधिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें से एफ०आई०आर० संख्या 56/2023 व 57/2023 वर्तमान घटना क्रम से संबंधित है। अभियुक्त बॉबी पंवार के विरुद्ध उपर्युक्त के अतिरिक्त दो एफ०आई०आर० मु०अ०सं० 40/2020 व 274/2022, थाना डालनवाला में दर्ज होना दिखाया गया है। बचाव पक्ष ने कथन किया गया है, एफ०आई०आर० संख्या 56/2023 में अभियुक्तगण की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मात्र एफ०आई०आर० दर्ज होना, अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास को दर्शित नहीं करता है। साक्ष्य से छेड़छाड़ करने तथा विवेचना प्रभाति करने के संबंध में अभियोजन ने कोई कथन नहीं किया है। यह कथन कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक की पुर्नावृत्ति की पूर्ण संभावना है। विदित हो, कि प्रकरण में धरना, प्रदर्शन में पथरावत आम जनता का आक्षेप है।

8. अभियुक्तगण का प्रथम रिमाण्ड 146,147,188, 324, 332,353,427,341 व 34 भा०दसं०, 1860, व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान का निवारण अधिनियम, तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्डमेंटे अधिनियम स्वीकार किया गया है। जिसमें से धारा 146,147,188 व 427 भा०द०सं०, 1860 को छोड़कर सभी धाराये अजमानतीय प्रकृति की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 10. 02.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला मजिस्ट्रेट, न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी परिस्थिति में मामले में गुण-दोष पर विचार किये बिना उपर्युक्त चर्चा के आधार पर यह न्यायालय सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार पाती है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 30,000/-रु० का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू दाखिल पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

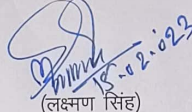
(क) प्रार्थी/अभियुक्त निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) प्रार्थी/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस बात की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे, कि वह किसी उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेंगे अथवा आंदोलन एवं सरकारी सम्पत्ति को नुकसान न किये जाने का कोई कारण नहीं बनें तथा बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन नहीं करेंगे।

उत्तराखण्ड क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिजर प्रेक्टिस रूल 2021, नियम 33 (यथा संशोधन) के अनुक्रम में कार्यालय को आदेशित किया जाता है, कि निरूद्ध अभियुक्त को, जरिये जेल अधीक्षक, जमानत प्रार्थनापत्र, आख्या व आदेश की प्रति प्राप्त कराये जाने हेतु, प्रेषित करना सुनिश्चित करे।


(लक्ष्मण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।